Hindi to English News Translation

सन् 1980 के आस–पास पश्चिमी देशों के बाजारों में फिर से मंदी का दौर शुरू हुआ। इस मंदी के दौर का सबसे बुरा असर अमरीका के ऊपर पड़ा। अमरीका की कई बड़ी–बड़ी कम्पनियाँ दिवालिया हो गयी। कई अमरीकी कारखाने बन्द हो गये। अमरीका में हजारों लोग बेरोजगार होने लगे। इसी तरह यूरोप में भी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। इस 80 के दशक की आर्थिक मंदी को दूर करने के लिये अमरीका ने फिर युद्ध का सहारा लिया। ईरान और ईराक के बीच लगभग 8 वर्षों तक चलने वाले युद्ध में अमरीकी कम्पनियों ने अरबो–खरबों डालर के हथियार बेच कर अपने उद्योगों की मन्दी को कम करने का प्रयास किया। इसी तरह खाड़ी युद्ध को भी अमरीका ने अपने हित में ही इस्तेमाल करके अरबों–खरबों डालर के हथियारों का व्यापार किया। हाल ही में अमरीका द्वारा अफगानिस्तान एवं ईराक पर किया गया हमला भी इसी रणनीती का हिस्सा है। यूरोपीय–अमरीकी अर्थव्यवस्था की एक सबसे बड़ी परेशानी यह है कि हर 30–40 साल बाद इसमें मंदी आती है। उस मंदी को दूर किये बिना इन अमरीकी–यूरोपीय देशों का गुजारा नहीं चलता है। इसलिये अमरीकी–यूरोपीय अर्थशास्त्रियों ने इस आर्थिक मंदी का स्थायी इलाज करने की कोशिशों में गैट करार को आधार बना लिया है। उद्देश्य यह है कि मंदी को दूर करने के लिये अमरीकी– यूरोपीय सामान दुनिया के तमाम देशों के बाजारों में बिकते रहें। अमरीकी एवं यूरोपीय बाजारों में एक तरह की स्थिरता आ चुकी है। इसलिये अमरीकी–यूरोपीय अर्थव्यवस्था को जीवित रखने के लिये, दूसरे देशों के बाजारों का सहारा लेना बहुत जरूरी है। अतः अमरीकी–यूरोपीय देशों की सरकारों ने गैट करार का उपयोग करके दूसरे देशों के बाजारों को और अधिक खुलवाने का प्रयास शुरू किया है।

सन् 1986 में गैट के सदस्य देशों की एक सामान्य सभा लैटिन अमरीका के एक देश उरूग्वे में शुरू हुयी। इस बैठक में अमरीका और यूरोपीय देशों की दादागिरी में गैट करार की सीमा को बढ़ाया गया। मूलतः 1948 से 1986 तक गैट एक बहुपक्षीय व्यापार का मंच था, तटकरों (सीमाशुल्क) का विवाद सुलझाने के लिये। लेकिन उरूग्वे दौर की वार्ताओं ने इसका स्वरूप पूरी रह से बदल दिया। गैट करार में सीमा शुल्क के मुद्दों के अलावा 28 और विषय शामिल कर दिये गये। जिसमें कृषि व्यापार, कपड़ा व्यापार, बौद्धिक सम्पदा अधिकार जैसे अवांछित विषय शामिल कर लिये गये। हालांकि इन विषयों पर कोई और समझौता होने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ये सभी विषय सभी देशों के आन्तरिक विषय हैं। गैट करार का 1948 से 1986 तक यह नियम रहा कि देशों के आन्तरिक विषयों को गैट करार के तहत नहीं लाना चाहिए। क्योंकि ये सभी विषय आन्तरिक सम्प्रभुता से जुड़े हुये हैं। लेकिन अमरीकी दबाव में आन्तरिक सम्प्रभुता से जुड़े हुये विषय भी शामिल कर लिये गये और एक नया समझौता तैयार हुआ। इस नये समझौते को तैयार करने के लिये जो टीम बनायी गयी, उस

Euro-American Strategy to tackle the Recession

Around the year 1980, recession started in the markets of Western countries. America was very badly affected due to this recession. Many big American companies had gone bankrupt. Many American industries were closed down. Thousands of employees lost their livelihood. Unemployment was very much prevalent in America. In the same manner, in other European countries too, the economic situation was worsening. In order to get rid of this recession of 1980, America again took the support of war as its sustenance. The American companies sold weapons of billions and trillions of dollars during the 8 years of war between Iran and Iraq, thus they tried to minimize the effects of the recession on American industry and economy. In the same, America utilized the Gulf war in its favour and sold weapons to the tune of billions and trillions of dollars. The recent attack on Afghanistan and Iraq also was a part of the same strategy. The Euro-American economic situation is such that in every 30-40 years period, they become victims of economic recession. Without getting rid of this recession, the Euro-American countries cannot survive. Hence, to get a permanent solution for this recession, the Economists of Euro-American countires have made the GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) Agreement a base for them. The purpose is to save themselves from the recession, selling the goods of Euro-American companies throughout the world. Now there is a sort of stability in the European and American companies. Hence, in order to keep the economic situation of the European and American companies alive, support of the markets of other countries is quite imperative for them. Therefore, the American and European Governemnts, started using the GATT Agreement in their favour to open many more new markets in all other countries.

The General Assembly of the member countries of GATT started in Uruguay, a Latin-American Country. The limits and conditions of GATT Agreement were expanded with the big brotherly behaviour (domination / highhandedness) of Euro-American Countries. Originally, from 1948 to 1986 GATT was a multilaterial trading platform for settlement of tariff (customs duty) disputes. But the negotiations during Uruguay rounds, change its nature completely. Apart from the Customs Duty issues, 28 more points were included in the GATT Agreements. In this, many unwanted issues like agricultural products, textile, border estate authority etc. were also included. Though there was no need of any other agreement on these issues, because these were the internal affairs of the respective countries. From 1948 to 1986, it was one of the rule of GATT that no internal matter of a country should be brought under GATT Agreement, because all of these issues are being related to internal affairs of a country. But due to the pressure of America, matters related to the internal sovereignty were also included and a new Agreement was prepared. The team to prepare this new agreement was ….